

जिस देश का इतिहास कुछ ढाई सौ साल का है, ने दो हजार साल पुरानी सभ्यता को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी

धमकी की पूर्ति में अमेरिका ने ईरान के खार्ग टापू पर बमबारी शुरू की तथा टापू पर स्थित ईरान सेना के डिपो व टर्मिनल पर भी बम बरसाए

-अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अप्रैल। ईरान, जो कि दो सहस्राब्दियों से अधिक पुरानी फारसी सभ्यता का जन्मस्थान है, को उस देश से विनाश की धमकी मिली है, जिसका इतिहास केवल 250 साल पुराना है और जो अपनी आग्नेय शक्ति पर गर्व करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक असभ्य धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी बमबारी ऐसी होगी कि पूरी सभ्यता को समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस विनाशकारी स्थिति से बचना चाहता है तो उसे अमेरिका के साथ समझौता करना होगा और होर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा।

- खार्ग टापू से ईरान का नब्बे प्रतिशत ऑयल निर्यात होता है।
- ईरान ने भी अमेरिका के मित्र देशों पर जवाबी बम वर्षा की तथा अमेरिका को अंगूठा दिखाते हुए कहा कि ईरान के 14 मिलियन निवासी अपने देश की सुरक्षा के लिए जान देने को तैयार हैं। प्रतीक के रूप में, ईरान के लोकप्रिय संगीतज्ञ, पावर प्लांट के सामने बैठे हैं, हाथ में ईरान के लोकप्रिय वाद्य बजाते हुए। जैसा कि विदित ही है, ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स, पुल आदि नष्ट करने की धमकी दे रखी है।
- खाड़ी में अमेरिका के मित्र देश, जिन्हें ईरानी ड्रोन्स व मिसाइल पहले से ही काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं, शिकायतें तो कर रहे हैं, पर इसके आगे कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं।
- पर, युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया है तथा युद्ध कर रहे देश, "डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाने का मन बना रहे हैं। इस रेंजिस्तानी इलाके में पानी के स्रोत बहुत कम हैं तथा डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स के सहारे ही पीने का पानी उपलब्ध होता है। अगर, ये प्लांट बम से उड़ा दिए गये तो युद्ध के भारी दुष्परिणाम होंगे।

बमबारी में पूरी सभ्यता समाप्त हो जायेगी। लेकिन ईरान ने ट्रंप की मांगों के आगे झुकने से इंकार कर दिया है। देश के राष्ट्रपति ने कहा कि 1.4 करोड़ ईरानी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर-रुके रहेंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट परिसर में वकीलों के लिए वाईफाई, वर्क स्टेशन और कॉमन बार रूम बनाने की मांग

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी को इस संबंध में पत्र लिखा

जयपुर, 7 अप्रैल (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी को पत्र लिखकर परिसर में अधिवक्ताओं के लिए वर्क स्टेशन बनाने, प्रिंटिंग व स्कैनिंग की सुविधाएं मुहैया करवाने, सरल व सहज उपलब्धता के जरिए हाई स्पीड वाई-फाई सुविधा और चाय-कॉफी के लिए रिफ्रेशमेंट एरिया विकसित करने, सुरक्षा गार्ड बैठाते तथा गेट नंबर 2 व 3 के पास गाड़ी पार्किंग हटाने समेत कई मुद्दों पर सुझाव दिए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यह पत्र कमेटी के अध्यक्ष कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और

- बिल्डिंग कमेटी के सदस्य जस्टिस समीर जैन व जस्टिस अशोक जैन ने बार एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि इन सुझावों के लिए जल्दी ही बैठक बुलाई जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

दूसरे सदस्य न्यायाधीश समीर जैन व न्यायाधीश अशोक कुमार जैन को लिखे हैं। जिस पर जस्टिस समीर जैन व जस्टिस अशोक जैन ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष अधिवक्ता राजीव सोगरवाल, महासचिव दीपेश शर्मा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता अनुराग कलावटिया को आश्वासन दिया है कि, उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। इस सुझाव पत्र में बार एसोसिएशन ने स्पॉट्स रूम फेसिलिटी को सुधारने, ई-वॉलक की कैंटीन को बेहतर करने, हाईकोर्ट परिसर में बैठने की सुविधा व कोर्ट रूम में मोबाइल व आईपैड की चार्जिंग सुविधा विकसित करने तथा कॉमन बार रूम बनाये जाने का सुझाव भी दिया गया है।

पवन खेड़ा के घर पहुँची असम पुलिस

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अप्रैल। असम पुलिस की एक टीम, दिल्ली पुलिस की

- खेड़ा पर असम के मु.मंत्री की पत्नी रिंकी भूहूयाँ ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, क्योंकि खेड़ा ने मु.मंत्री हिमंता की पत्नी रिंकी भूहूयाँ पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। इसलिए खेड़ा की तलाश में पुलिस उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुँची।

एक टीम के साथ मंगलवार सुबह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

युद्ध समाप्ति के लिए ईरान का 10 सूत्रीय प्लान

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अप्रैल। राष्ट्रपति ट्रंप की 15-बिंदु की 'शांति' योजना के जवाब में ईरान ने 10-बिंदु की प्रस्तावित योजना पेश की है, जो उचित प्रतीत होती है और जो पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए तैयार की गई है।

- इसमें ईरान पर भविष्य में हमला नहीं करने की गारंटी और अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है।

यह केवल संघर्षविराम के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को समाप्त करने के लिए है। ईरान की 10-बिंदु योजना इस प्रकार है:

1. यह गारंटी दी जाए कि ईरान पर फिर कभी हमला नहीं किया जाएगा।
2. केवल संघर्षविराम नहीं, बल्कि युद्ध का स्थायी अंत होगा।
3. लेबनान में इजरायली हमलों का अंत किया जाए।
4. ईरान पर लगे सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाया जाए।
5. ईरानी सहयोगियों के खिलाफ सभी क्षेत्रीय लड़ाइयों का अंत हो।
6. इसके बदले में, ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोल देगा।
7. ईरान प्रत्येक जहाज से होर्मुज शूल्क के रूप में 2 मिलियन डॉलर लेगा।
8. ईरान इन शूल्कों को ओमान के साथ साझा करेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा के संगठन की ताप, से बनर्जी भी बौखलायीं

वे तरह-तरह की, विरोधाभासी साजिश की थ्योरी खूब प्रचारित कर रही हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अप्रैल। पश्चिम बंगाल चुनावों के समापन के बाद विपक्ष की एकता को फिर से जीवित करने के लिए देशभर में यात्रा की योजना की घोषणा करते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रियो ने मंगलवार को उस समय अपने लिए खुद ही मुश्किल खड़ी कर ली, जब उन्होंने कांग्रेस, द्रमुक, उसके नेता एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु की सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के अन्य घटक दलों पर भाजपा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया।

ऐसे समय पर इस विचित्र षड्यंत्र सिद्धांत, जब दक्षिणी राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर है, के चलते क्षेत्रीय दलों के नेताओं में बनर्जी की नेतृत्व क्षमता के प्रति आत्मविश्वास पैदा होने की संभावना कम है। यह धारणा और बढ़ गई है कि भाजपा के आक्रामक स्वयं का सामना करते हुए, बनर्जी अजीब और असामान्य विचार प्रस्तुत कर रही थीं। नदिया जिले में एक चुनावी रैली में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल कैडर के कई आईएस और आईपीएस अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा तमिलनाडु में पर्यवेक्षक के रूप में भेज दिये गये हैं, जिससे बंगाल में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "आप (भाजपा) का कांग्रेस और स्टालिन के साथ निश्चित रूप से कोई

- एक तरफ तो वे चुनाव के बाद पूर्ण विपक्ष में एकता का नारा देकर पूरे देश का दौरा करने की योजना बना रही हैं।
- दूसरी ओर वे दक्षिण भारत के विपक्ष की सरकारों पर आरोप लगा रही हैं, विशेषकर तमिलनाडु व केरल की पार्टियों पर, कि वे भाजपा से, मोदी से मिल गई हैं। क्योंकि, बंगाल के 500 प्रशासनिक अधिकारियों को बंगाल से बाहर पोस्ट किया है, केन्द्र की भाजपा सरकार ने और तमिलनाडु व केरल सरकार ने बंगाल के अफसरों को अपने यहाँ चुनाव के दौरान पोस्टिंग देकर बिना विरोध किये स्वीकार कर लिया है।
- कुछ दिन पहले उन्होंने एक और साजिश की बात कही थी कि भाजपा सरकार एक और पहलगाय काण्ड कराएगी, बंगाल में मतदान से पहले।

मौन समझौता है। अन्य चुनावी राज्यों (तमिलनाडु, केरल और असम) में केवल कुछ अधिकारियों का तबादला हुआ, जबकि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बंगाल के लगभग 500 अधिकारियों का तबादला बंगाल से बाहर कर दिया गया है। उसी रैली में बनर्जी ने बड़ा कार्यक्रम भी घोषित किया: बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद टीएमसी दिल्ली में भाजपा को निशाना बनाएगी। मैं देशभर में यात्रा कर विपक्ष की एकता कायम करूँगी। हम सभी पार्टियों को साथ लेंगे।

पान मसाला विज्ञापन को लेकर सलमान खान और निर्माता कंपनी को राहत

हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी जमानती वारंट पर रोक लगाई

-यादवेन्द्र शर्मा-
जयपुर, 7 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजश्री पान मसाला के ग्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान व अन्य के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने विज्ञापन करने पर रोक लगाने के आदेश पर भी रोक लगाई है। जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपिठ ने यह आदेश सलमान खान और निर्माता कंपनी कमलाकांत एंड कंपनी एलएलपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में जिला आयोग द्वारा 6 जनवरी और 15 जनवरी तथा राज्य आयोग के 16 मार्च के आदेशों को चुनौती दी गई है। इस मामले में

- राजश्री पान मसाला और अभिनेता सलमान खान की ओर से अधिवक्ताओं ने पैरवी करते हुए कहा कि, "योगेन्द्र सिंह ने अपनी याचिका में जिन विज्ञापनों की बात की थी, वह पान मसाला ना होकर सिल्वर कोटेड इलायची से संबंधित थे।"
- हाईकोर्ट ने माना कि जिला उपभोक्ता मंच के पास ऐसी शिकायतें सुनने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने राजश्री पान मसाला और अभिनेता सलमान खान का पक्ष सुने बिना ही विज्ञापन बंद करने के आदेश दिए थे, जो कि गलत है।
- हाईकोर्ट ने कहा कि "जब जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष राजश्री पान मसाला व अभिनेता सलमान की ओर से अधिवक्ता पैरवी के लिए मौजूद थे, इसके बावजूद भी जमानती वारंट जारी करना और यह कह देना कि अभिनेता सलमान खान के हस्ताक्षर मैच करवाए जाएं, पूरी तरह अवैध है।"

सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एन. बापना व उनके सहायक अधिवक्ता शिवांगु नवल, पराग खंडर, ज़ारा और चंद्रिमा पैरवी के लिए पेश हुए थे। वहीं राजश्री पान मसाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी.सिंह व उनके सहायक अधिवक्ता वरुण सिंह और देवेश शर्मा पैरवी के लिए पेश हुए थे। याचिकाओं में अदालत को बताया गया कि योगेन्द्र सिंह ने जिला आयोग में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन का इस्तीफा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अप्रैल। एयर इंडिया ने मंगलवार को अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) और प्रबंध निदेशक कैम्पबेल विल्सन के इस्तीफे की पुष्टि की। एयरलाइन ने एक

- एयर इंडिया ने इस्तीफे की पुष्टि की, पर उत्तराधिकारी मिलने तक कैम्पबेल अपने पद पर काम करते रहेंगे।

आधिकारिक बयान में कहा कि आने वाले महीनों में उनके उत्तराधिकारी को ढूँढने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। न्यूजीलैंड में जन्मे विल्सन ने 2022 में एयरलाइन के निजीकरण के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पश्चिम एशिया वॉर बढ़ने का खतरा बढ़ा, ईरान ने लिया मुकाबले का संकल्प

ईरान ने साफ कर दिया है कि वह दबाव में समझौता नहीं करेगा और अमेरिका भी बड़ी डींगें हांक चुका है, इसलिए वह भी पीछे नहीं हट रहा है, फिलहाल कोई कूटनीतिक हल नज़र नहीं आ रहा है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अप्रैल। यूएस-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे 39 दिनों पुराने युद्ध के तेज और अस्थिर चरण में प्रवेश करने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि तेहरान की लौह-निष्पक्ष से मुकाबला करने की नीति से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नाराजगी बढ़ गई है। वॉशिंगटन ने मौत, विनाश और तबाही की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। जहां तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह दबाव में कोई वार्ता नहीं करेगा, वहीं वॉशिंगटन के लिए अपने लम्बे-चौड़े दावों से पीछे हटना कठिन साबित हो रहा है। रात भर चले संदेशों से स्थिति बिगड़ी है और ऐसा कोई संकेत नहीं

- मुकाबला करने का संकल्प ले चुके तेहरान ने अपने नागरिकों से एक "असाधारण" अपील कर डाली। ईरान के डैप्युटी स्पोट्स मिनिस्टर अलीरेज़ा रहीमी ने एथलीट्स, कलाकारों और छात्रों से अपील की है कि वे ऊर्जा संयंत्रों के चारों तरफ "ह्यूमन चैन" बना लें ताकि अमेरिका हमला न कर पाए। एक वीडियो संदेश में रहीमी ने यह अपील की और कहा, ये संयंत्र हमारी सम्पत्ति हैं। उन्होंने नागरिकों से इसकी रक्षा करने की अपील की।
- अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए मंगलवार की समय सीमा तय की थी। उन्होंने कहा, अगर तेहरान ने अनुकूल जवाब नहीं दिया तो अमेरिकी सेना ऊर्जा संयंत्रों और पूर्णों पर एक साथ हमला कर देगी। हम ईरान को पाषाण युग में पहुँचा देंगे।
- इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने बुशहर परमाणु केन्द्र के पास मिसाइल गिरने पर चिंता जताई, उन्होंने कहा कि एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाना चाहिए।

मिला है कि तुरंत कोई कूटनीतिक पहल हो सकती है। जैसे-जैसे अमेरिका द्वारा निर्धारित समय सीमा नज़दीक आ रही है, यह संघर्ष अब केवल हमलों और जवाबी हमलों तक सीमित नहीं रहा। यह अब तेल मार्ग, सिविलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर और व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों तक फैल गया है। इस सब के केन्द्र में होर्मुज स्ट्रेट है और आगे क्या होगा, उससे ही आने वाले दिनों की स्थिति तय होगी।

डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बढ़ते हुए, तेहरान ने अपने नागरिकों से एक असामान्य अपील की है। ईरान के

उप खेल मंत्री अल्लिरेज़ा रहिमी ने खिलाड़ियों, कलाकारों और छात्रों से आग्रह किया है कि वे प्रमुख बिजली संयंत्रों के आसपास इकट्ठा हों और मानव श्रृंखला बनाकर किसी भी संभावित अमेरिकी हवाई हमले को हतोत्साहित करें। यह अपील ऐसे समय आई है, जब वॉशिंगटन ने होर्मुज स्ट्रेट को पुनः खोलने के लिए तेहरान को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान मंगलवार शाम अमेरिकी समय तक अनुपालन नहीं करता, तो उसे देश भर में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रूस और चीन खुलकर ईरान के पक्ष में आये

न्यूयॉर्क, 08 अप्रैल। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच मंगलवार को अमेरिका को झटका लगा है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसका मकसद होर्मुज स्ट्रेट

- सुरक्षा परिषद में अमेरिका के होर्मुज खोलने के प्रस्ताव को वीटो किया।

को फिर से खोलना था। यह प्रस्ताव ऐसे समय में पारित नहीं हो सका, जब ईरान से समझौते के लिए अमेरिका की समय सीमा नज़दीक आ रही है। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। सुरक्षा परिषद के 15 में से 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। पाकिस्तान और कोलंबिया ने मतदान से दूरी बनाई। ज़रूरी नौ वोट मिल गए थे। फिर भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। रूस और चीन स्थायी सदस्य हैं। उनके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)